बजट 2025-26 की मुख्य बातें

- दिल्ली सरकार का बजट 2025-26 - ₹ 1,00,000 करोड़
  - योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत बजट - ₹ 59300 करोड़
  - स्थापना बजट - ₹ 40700 करोड़
  - राजस्व बजट - ₹ 71,885 करोड़
  - पूंजीगत बजट - ₹ 28,115 करोड़
- 2025-26 में ₹ 1,00,000 करोड़ का बजट अनुमान 2024-25 के ₹ 76000 करोड़ से 31.5% अधिक है और 2024-25 के संशोधित अनुमान ₹ 69500 करोड़ से 44% अधिक है।
- वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट ₹100000 करोड़ का वित्तपोषण ₹68700 करोड़ के कर राजस्व, ₹750 करोड़ के गैर-कर राजस्व, ₹15000 करोड़ के लघु बचत ऋण, ₹1000 करोड़ के केन्द्रीय सड़क निधि, ₹4128 करोड़ की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, ₹7348 करोड़ के भारत सरकार से सहायता अनुदान तथा शेष राशि प्रारंभिक शेष से किया जाना है।
- प्रस्तावित बजट 2025-26 का 72% राजस्व व्यय तथा 28% पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है।

सरकार के दस मुख्य संकल्प

1. Infrastructure Development– बुनियादी सुविधाओं–पानी, बिजली व सड़क का विकास

i) दिल्ली ट्रैफिक-फ्री एक्सप्रेसवे, सीमलेस कनेक्टिविटी, एलिवेटेड कॉरिडोर और स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम के एक नए युग में प्रवेश कर रही है।

ii) केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) और भारत सरकार के शहरी विकास निधि (यूडीएफ) आदि के तहत उपलब्ध निधियों के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ₹ 1000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

iii) दिल्ली में मौजूदा 2,80,000 कैमरों के अलावा 50,000 कैमरे लगाना।

iv) दिल्ली में सड़क और पुल के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए ₹ 3843 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

v) ₹ 1400 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ एक नई योजना 'मुख्यमंत्री विकास निधि' शुरू करना। इस योजना का उद्देश्य विकास और सहायता के लिए धन आवंटित करना है तथा यह सरकार की अन्य योजनाओं और पहलों के तहत पहले से किए गए प्रयासों को अनिवार्य रूप से पूरक बनाएगी।

vi) 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए केंद्र द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत ₹ 1000 करोड़ का प्रस्ताव।

vii) मलिन बस्तियों और जेजे कॉलोनियों के विकास के लिए डीयूएसआईबी को ₹ 696 करोड़ आवंटित करना, जो पिछले वर्ष की तुलना में 157% अधिक है।

viii) सीसी फुटपाथ, नालियों, शौचालयों, रखरखाव कार्यों और महिलाओं के लिए बाथरूम जैसे बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए ₹ 230 करोड़, जबकि पिछले वर्ष ₹ 42 करोड़ थे।

ix) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभ प्रदान करने के लिए ₹ 20 करोड़ का प्रस्ताव।

x) बजट 2025-26 में एमएलए-एलएडी के तहत 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो सड़कों, गलियों, स्थानीय पार्कों, स्ट्रीट लाइट आदि जैसे बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए प्रदान किया जाएगा।

xi) स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी तक दिल्ली में 100 स्थानों पर पौष्टिक और रियायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2. Industrial Development and Investment Promotion– उद्योग और निवेश - समृद्धि का रास्ता, प्रगति का आधार

i) दिल्ली को देश में व्यापार और निवेश के लिए सबसे अनुकूल केंद्र बनाना।

ii) दिल्ली के लिए एक नई औद्योगिक नीति लाना।

iii) वेयरहाउसिंग नीति को भी अंतिम रूप दिया जाएगा जो दिल्ली में सुरक्षित, संरक्षित और तेज़ वेयरहाउसिंग प्रदान करने के लिए उद्योगों की बड़ी ज़रूरत को पूरा करेगी।

iv) 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा।

v) अवैध और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से "ज़ीरो टॉलरेंस" नीति के तहत निपटा जाएगा।

vi) एक व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करना, जो दिल्ली में व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने पर काम करेगा।

vii) कुटीर उद्योगों जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, लघु हस्तशिल्प और हथकरघा गतिविधियां, लघु खाद्य प्रसंस्करण आदि के कौशल संवर्धन के लिए नई योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका क्रियान्वयन दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

viii) 2025-26 में निवेश शिखर सम्मेलन की योजना बनाई गई है, जो उसके बाद हर दो साल में आयोजित किया जाएगा।

3. Access to Water, Sanitation, and Yamuna Cleaning- स्वच्छता, शुद्ध पानी, स्वच्छ यमुना का अभियान, बनेगा दिल्ली की पहचान

i) दिल्ली के हर नागरिक को स्वच्छ जल और स्वच्छता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसके तहत जल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए 9,000 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक योजना बनाई गई है।

ii) दिल्ली की 3 करोड़ आबादी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना।

iii) पानी के टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाना और एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप "डीजेबी टैंकर" विकसित करना, जिसके जरिए नागरिक अपने इलाके में आने वाले टैंकरों की निगरानी और ट्रैकिंग कर सकेंगे।

iv) 10 करोड़ रुपये की लागत से जल क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाएं लेना।

v) जल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्वचालन, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) प्रणाली और इंटेलिजेंट मीटरिंग में 150 करोड़ रुपये का निवेश करना।

vi) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की मरम्मत और विकास के लिए ₹ 500 करोड़, पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिए ₹ 250 करोड़ और जल उपचार संयंत्रों के सुधार के लिए ₹ 250 करोड़।

vii) सीवरेज प्रणाली में सुधार के लिए सुपर सकर और डिकी मशीनों की खरीद के लिए ₹ 20 करोड़। viii) वजीराबाद ट्रंक सीवर के नवीनीकरण के लिए ₹ 10 करोड़ आवंटित।

ix) दिल्ली में गंदे नाले के पानी को रोकने और उसका उपचार करने के लिए ₹ 250 करोड़।

x) सी.एल.सी. नाले की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये, जलापूर्ति से वंचित क्षेत्रों में पाइप से जलापूर्ति के लिए 50 करोड़ रुपये तथा नजफगढ़ नाले के रूपांतरण और अवरोधन के लिए 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

xi) जल हानि को रोकने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हरियाणा से खुली नहरों के स्थान पर 200 करोड़ रुपये की लागत से पाइपलाइन बिछाई जाएगी।

xii) 100 करोड़ रुपये की लागत से नए बोरवेल/रैनीवेल स्थापित करना।

xiii) दिल्ली के जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित।

xiv) वर्षा जल संचयन के लिए 50 करोड़ रुपये तथा आपातकालीन जल भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित।

xv) यमुना जी की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से 40 विकेन्द्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण करना, ताकि सीवेज जल का उपचार स्रोत पर ही किया जा सके।

xvi) आधुनिक मशीनरी की खरीद के लिए ₹ 40 करोड़, जिसमें ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर, ड्रेज यूटिलिटी जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं।

xvii) भारत सरकार से ₹ 2,000 करोड़ की वित्तीय सहायता की मांग करना, क्योंकि दिल्ली के जल और सीवेज बुनियादी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए और अधिक सहायता की आवश्यकता है।

4. Health and Education For All- शिक्षा गुणवत्तापूर्ण, स्वास्थ्य का विस्तार, बनेगा दिल्ली के भविष्य का आधार

i) वर्तमान में, दिल्ली में एक हजार की आबादी के लिए 2.70 बिस्तर उपलब्ध हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड के अनुसार एक हजार की आबादी के लिए 5 बिस्तर उपलब्ध हैं।

ii) 24 अस्पतालों की लंबित परियोजनाओं को पूरा करना, जिसके पूरा होने के बाद दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 16,186 बिस्तर और जुड़ जाएंगे।

iii) 400 एचडब्ल्यूसी/आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) की स्थापना के साथ बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी)/आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के विस्तार के लिए ₹ 320 करोड़ का प्रस्ताव।

iv) पीएम-एबीएचआईएम योजना के लिए ₹ 1666.66 करोड़ का प्रस्ताव, जिसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और डायग्नोस्टिक्स को मजबूत किया जाएगा।

v) एबी-पीएमजेएवाई के तहत वित्तीय सुरक्षा के लिए कवरेज बढ़ाने के लिए ₹ 147.64 करोड़ का आवंटन।

vi) स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के लिए ₹ 9.92 करोड़ का प्रस्ताव।

vii) वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा की दिशा में काम करने के लिए दिल्ली राज्य आयुष सोसायटी (डीएसएएस) को लागू करना।

viii) आगामी सत्र 2025-26 से पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर 60 नए सीएम श्री स्कूल खोलने के लिए ₹ 100 करोड़ का प्रस्ताव, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पूर्ण अनुपालन में होंगे और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफएससी) 2023 को लागू करेंगे।

ix) महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन शुरू करने के लिए 21 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी, जिसके तहत JEE, NEET, CLAT, CA और CUET परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पेशेवर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

x) दिल्ली सरकार के KG से कक्षा 12 तक के छात्रों को शामिल करते हुए 'राष्ट्रनीति' कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शासन, लोकतंत्र, सक्रिय नागरिकता और नीति निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है।

xi) दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में 21 करोड़ रुपये के बजट से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भाषा प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँगी।

xii) KG से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए 'साइंस ऑफ लिविंग' कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

xiii) सरकारी स्कूलों में 175 नई कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।

xiv) शिक्षा निदेशालय के लिए कक्षा 9 से 12 तक सभी कक्षाओं में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करना, जो चरणबद्ध तरीके से कुल 7,000 कक्षाओं को कवर करेगा। पहले चरण में वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए ₹ 100 करोड़ प्रस्तावित हैं, जिसमें लगभग 2000 कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित किया जाएगा।

xv) कक्षा 10 बोर्ड के परिणामों के आधार पर कक्षा 11 के 1,200 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने के लिए ₹ 7.5 करोड़।

xvi) छात्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था में आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए कक्षा 8 से कक्षा 12 तक सभी स्कूलों में NEEEV (उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र और विजन का नया युग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए ₹ 20 करोड़।

xvii) तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए 618.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जिनमें डीएसईयू के लिए 230 करोड़ रुपये, एनएसटीयू के लिए 57 करोड़ रुपये, डीपीएसआरयू के लिए 37 करोड़ रुपये, आईजीडीटीयू फॉर वूमेन के लिए 21.50 करोड़ रुपये और डीटीयू के लिए 42 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आईटीआई के लिए 68.98 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

xviii) नरेला उप-शहर में एजु-सिटी स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये, जिसके लिए डीडीए ने भूमि आवंटित की है - (i) आईजीडीटीयूडब्ल्यू को 160 एकड़, और (ii) चार विश्वविद्यालयों अर्थात् डीटीयू, डीएसईयू, डीपीआरएसयू, जीजीएसआईपीयू को 1270 फ्लैट, ताकि वे नरेला में अपने परिसरों की स्थापना या विस्तार कर सकें।

xix) आईटीआई पूसा परिसर के पुनर्विकास और आईटीआई शाहदरा परिसर के निर्माण के लिए ₹ 20.65 करोड़।

xx) यथासंभव कुशल लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान करना और उन्हें मानकीकृत प्रमाणन प्रक्रिया और विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जाने वाले अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से औपचारिक/संगठित क्षेत्र में लाना।

xxi) युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, स्टार्ट-अप स्थापित करने और उन्हें नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाता बनाने की क्षमता विकसित करने के लिए राज्य इनक्यूबेशन नीति के तहत 11 इनक्यूबेशन केंद्रों के लिए ₹ 2.43 करोड़ का प्रस्ताव।

5. Tourism, Art, Language and Culture Promotion– 'विरासत भी और विकास भी' की सोच के साथ दिल्ली को विश्व पर्यटन केंद्र बनाना

i) दिल्ली को विश्व पर्यटन केंद्र बनाने के लिए पर्यटन क्षेत्र की योजनाओं के लिए 117 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि पिछले साल यह 66 करोड़ रुपये था।

ii) सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक यमुना नदी में नाव यात्रा का आयोजन पीपीपी मोड पर किया जाएगा, जिसके लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और डीडीए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

iii) पर्यटन को बढ़ावा देने और दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

iv) पर्यटन के विशिष्ट और उभरते क्षेत्रों में युवा पेशेवरों को तैयार करने के लिए फेलोशिप कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 2 करोड़ रुपये।

v) दिल्ली को फिल्म गंतव्य के रूप में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने के लिए 30 करोड़ रुपये।

vi) युद्ध स्मारक, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय और नए संसद भवन को शामिल करते हुए एक नया पर्यटन सर्किट विकसित करना।

vii) सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाद्य महोत्सव, संगीत समारोह आदि जैसे कार्यक्रमों के साथ एक वार्षिक शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

viii) छिपी हुई प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें मंच प्रदान करने, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और कलाकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नई "प्रतिभा खोज योजना" के लिए 5 करोड़ रुपये।

ix) मैथिली-भोजपुरी अकादमी के लिए बजट आवंटन 3.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.30 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।

6. Expanding Social Security and Development– गरीब एवं वंचित परिवारों को केवल सहारा नहीं, शक्ति भी और विकास भी

i) सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के लिए कुल ₹ 10,047 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से ₹ 9,780 करोड़ समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास और एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं।

ii) वरिष्ठ नागरिकों (60-69 वर्ष) के लिए मासिक सहायता बढ़ाकर ₹ 2,500/- की जा रही है; 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को ₹ 3,000/- की मासिक सहायता दी जाएगी। एससी/एसटी/अल्पसंख्यक समुदायों के वरिष्ठ नागरिकों (60-69 वर्ष) को ₹ 500/- की अतिरिक्त मासिक सहायता मिलेगी। संकटग्रस्त महिलाओं और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी ₹2,500/- से बढ़ाकर ₹3,000/- प्रति माह किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए ₹3,227 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

iii) वरिष्ठ नागरिकों को विश्राम और सामाजिक गतिविधियों के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 'वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन केंद्रों को जीआईए' योजना के तहत ₹20 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

iv) ₹5,100 करोड़ के बजट के साथ "महिला समृद्धि योजना" शुरू करना जिसके तहत पात्र महिलाओं को ₹2,500 की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस कदम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता और आत्म-सम्मान को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

v) चल रहे कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)' को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना' के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इस योजना के तहत कुल लाभ राशि बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगी तथा 6 पोषण किट भी दिए जाएंगे।

vi) 'पालना-राष्ट्रीय क्रेच योजना' के लिए ₹ 50 करोड़ का प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत 500 पालना-आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केंद्र चालू किए जाएंगे, ताकि माताएं अपने बच्चों के जन्म के बाद भी कार्यबल का हिस्सा बनी रहें।

vii) 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए इन आंगनवाड़ी केंद्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे, आधुनिक सुविधाओं और उच्च स्तरीय सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए ₹ 206 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। ये आंगनवाड़ी केंद्र अन्य सरकारी भवनों के साथ स्थित होंगे और पास के सरकारी स्कूलों से भी जुड़े होंगे, ताकि बच्चों को आसानी से नियमित स्कूलों में स्थानांतरित किया जा सके।

viii) दिल्ली में चल रहे 14 कामकाजी महिला छात्रावासों के अलावा 2 नए 'सखी निवास' शुरू किए जाएंगे, जिनमें 1,935 महिलाएं इन सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं।

ix) दिल्ली में बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए ₹ 5 करोड़ आवंटित।

x) नई योजना 'डॉ. बी. आर. अंबेडकर वजीफा योजना' के तहत अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए आईटीआई, कौशल केंद्रों और दिल्ली के पॉलिटेक्निक में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा।

xi) डीएसएफडीसी में सुधार के लिए 'डीएसएफडीसी के पुनरुद्धार के लिए जीआईए' योजना के तहत 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

xii) दिल्ली के हर गांव और किसान को सशक्त बनाने के लिए विकास विभाग को 1,157 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

xiii) 'पीएम किसान सम्मान निधि-राज्य टॉप-अप योजना' के तहत 4.85 करोड़ रुपये, जिसके तहत किसानों को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के तहत 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता के अलावा 3,000 रुपये सालाना (1,000 रुपये की तीन किस्तों में) दिए जाएंगे।

xiv) दिल्ली के घुमनहेड़ा गांव में आधुनिक सुविधाओं से लैस 'मॉडल गौशाला' स्थापित करने के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

xv) दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गांवों में समग्र विकास के लिए सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये।

7. Seamless Connectivity- सार्वजनिक परिवहन का नया दौर

i) वित्त वर्ष 2025-26 तक 2,152 इलेक्ट्रिक बसों वाले इलेक्ट्रिक बस बेड़े में 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल करना, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा हासिल करना है।

ii) चरण-4 के संतुलित 03 कॉरिडोर यानी लाजपत नगर - साकेत जी ब्लॉक, इंद्रलोक - इंद्रप्रस्थ, रिठाला - बवाना - नरेला - नाथूपुर (कुंडली) के काम के लिए दिल्ली मेट्रो के लिए ₹ 2929.66 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिन्हें 2025-26 में शुरू किया जाएगा।

iii) भारत सरकार के वित्त पोषण के साथ केंद्रीय वित्त पोषित शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए ₹ 1,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

iv) दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 12,952 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

8. Efficient Irrigation and Flood Control- सिंचाई में सुधार, बाढ़ का समाधान, सुरक्षित होगी राजधानी की जान

i) जलभराव और खराब जल निकासी व्यवस्था दिल्ली में एक गंभीर समस्या रही है, जिसके कारण हर साल बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है। सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आईएंडएफसी विभाग के लिए कुल ₹ 603 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

ii) बाढ़ नियंत्रण के लिए नालों की रीमॉडलिंग की महत्वाकांक्षी योजना ₹150 करोड़ के बजट के साथ प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य नालों की जल वहन क्षमता को बढ़ाना है, ताकि बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या को रोका जा सके।

iii) बाढ़ नियंत्रण के लिए खुले जल निकायों की सफाई और गाद निकालना।

iv) जलभराव और बाढ़ नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक मशीनरी खरीदी जाएगी।

9. Power, Sustainable Development, Green Growth and Pollution Control- हरित दिल्ली, स्वच्छ हवा, सतत विकास

i) विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए बिजली विभाग को ₹ 3,847 करोड़ आवंटित किए गए।

ii) दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना।

iii) सरकार दिल्ली में 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' को लागू करने के लिए भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। इस योजना के तहत, दिल्ली के आवासीय उपभोक्ताओं को ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

iv) एक नई योजना 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना - राज्य टॉप अप' भी प्रस्तावित है, जिसका बजट ₹50 करोड़ है, जिसके तहत अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख आवासीय छतों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित किया जाएगा।

v) "तारों के जाल से मुक्ति" के विजन के साथ, सरकार आने वाले वर्षों में बिजली के बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता और स्वच्छता बढ़ाने के लिए दिल्ली से ओवरहेड केबलों के जाल को हटाने की योजना बना रही है, जिसके लिए 2025-26 में ₹ 100 करोड़ का प्रस्ताव है।

vi) वायु और जल प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए, पर्यावरण और वन विभागों को पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी और परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए ₹ 506 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

vii) दिल्ली में पर्यावरण सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए "प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपायों" के तहत 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

viii) आरडब्ल्यूए, एनजीओ और सोसायटियों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने और दिल्ली के पार्कों और उद्यानों को हरा-भरा बनाने के लिए "दिल्ली पार्क और गार्डन सोसायटी" योजना के तहत 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

ix) पूरे शहर में बड़े पैमाने पर 70 लाख पौधे लगाने का अभियान चलाया जाएगा और साथ ही दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और शहरी जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

x) वायु प्रदूषण की वास्तविक समय की निगरानी और डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए दिल्ली में रणनीतिक स्थानों पर 6 नए सीएएक्यूएम (निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी) स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

xi) पहली बार दिल्ली में यमुना नदी और विभिन्न नालों में 32 जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ताकि जल गुणवत्ता की वास्तविक समय की निगरानी की जा सके।

xii) दिल्ली में एक "एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी)" स्थापित करना।

10. Smart and Good Governance– 'Perform, Reform and Transform' मंत्र के साथ सुशासन

i) "जिला परियोजना निधि योजना" के लिए ₹ 53 करोड़, छोटे पैमाने के कार्यों के लिए जिन्हें त्वरित वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

ii) बेहतर संकट प्रबंधन के लिए एकल आपातकालीन नंबर प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) प्रस्तावित है। डीडीएमए के तहत कमांड कंट्रोल सेंटर, ईओसी की स्थापना के लिए ₹ 30 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

iii) वित्त वर्ष 2025-26 में स्थानीय निकायों को ₹ 6897 करोड़ प्रस्तावित हैं। इसमें से ₹ 3,560 करोड़ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के लिए होंगे। ₹ 3,337 करोड़ बेसिक टैक्स असाइनमेंट (बीटीए) के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा ₹ 3,640 करोड़ स्टांप और पंजीकरण शुल्क और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रूप में दिए जाएंगे।

iv) दिल्ली में मौजूदा 690 कोर्ट हॉल में 200 और कोर्ट रूम जोड़कर कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 490 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान, खासकर शास्त्री पार्क, कड़कड़डूमा और रोहिणी में।

v) हाइब्रिड कोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपये।

vi) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सहयोग से, सरकार समर्पित POCSO अदालतों के माध्यम से संवेदनशील मामलों को संभालने वाले न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है ताकि बाल पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके और विशेष NDPS अदालतों के माध्यम से ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ सुनवाई में तेजी लाई जा सके।

vii) वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न न्यायिक योजनाओं के लिए ₹ 927 करोड़ का बजट रखा गया है।

viii) दिल्ली अग्निशमन सेवाओं की प्रतिक्रिया समय और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए भीड़भाड़ वाले और दूरदराज के क्षेत्रों में 100 स्थानों पर छोटी दमकल गाड़ियां तैनात करना।

ix) 17 वाटर बॉवर की खरीद के लिए ₹ 110 करोड़ आवंटित किए गए। दिल्ली अग्निशमन सेवाओं के तहत वाहनों में लाइव कैमरे लगाने के साथ-साथ मल्टी आर्टिकुलेटेड फायर टावर, एरियल लैडर प्लेटफॉर्म, हैज़मैट वैन आदि जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण।

x) दिल्ली में होमगार्ड स्वयंसेवकों की अधिकृत संख्या मौजूदा 10,285 से बढ़ाकर 25,000 करना। अतिरिक्त 15000 होमगार्ड स्वयंसेवक दिल्ली पुलिस, डीटीसी और अन्य विभागों के समन्वय से सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देंगे।

xi) दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को समयबद्ध तरीके से नौकरी देने के उद्देश्य से नौकरी मेलों के आयोजन के लिए ₹ 2 करोड़ आवंटित किए गए।

xii) गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, घरेलू सहायकों, ऑटो टैक्सी चालकों आदि के कल्याण के लिए अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करने हेतु ₹ 10 करोड़।

xiii) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के तहत शिकायतों के प्रभावी और समय पर निवारण के लिए दिल्ली 311 ऐप विकसित करने के लिए ₹ 15 करोड़ का प्रस्ताव है।

xiv) विभिन्न क्षेत्रों से नए युवा दूरदर्शी लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री युवा दूरदर्शी नवाचार कार्यक्रम' शुरू करने के लिए ₹ 10 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

xv) दिल्ली जेल के तत्वावधान में एक सोसायटी स्थापित की जाएगी। जो विभिन्न कौशल प्रदान करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से कैदियों के समग्र कौशल को विकसित करके उनके सुधार और पुनर्वास के लिए काम करेगी और जेलों के विभिन्न कारखानों और विनिर्माण इकाइयों के कामकाज को पेशेवर बनाएगी।

xvi) कैदियों के कल्याण के लिए मौजूदा तिहाड़ जेल परिसर को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करके नए जेल परिसर का विकास करके भीड़भाड़ को कम करना। परामर्श और सर्वेक्षण कार्य के लिए ₹ 10 करोड़ प्रस्तावित हैं।

xvii) 01-04-2025 से 'लामपुर प्रतिबंध / निरोध केंद्र का नवीनीकरण और परिवर्तन' इस योजना के तहत ₹ 20 करोड़ प्रस्तावित हैं।

सरकार के Vision में अन्य योजनाएँ

1. मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना
2. योजना का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचना चाहिए।
3. दिल्ली में दो मेडिकल कॉलेज खोले जाएँगे
4. राज्य अतिथि गृह की आवश्यकता पूरी की जाएगी।
5. दिल्ली में ऑडिटोरियम और स्टेडियम खोले जाएँगे
6. आनंद विहार आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी का पुनर्विकास किया जाएगा और दिल्ली के द्वारका में एक नया आईएसबीटी खोला जाएगा।

****